

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 534

भोपाल, बुधवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2017—आश्विन 12, शक 1939

वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 04 अक्टूबर 2017

क्र. 256-25-2017-आनीविइ-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ तथा अनुच्छेद 243-म के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के अनुसरण में, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 66-25/2017-आनीविइ-चार, दिनांक 20 मार्च 2017 की निरंतरता में मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पांचवें राज्य वित्त आयोग के विचारण हेतु निम्नलिखित कार्य अवधारित करते हैं, अर्थात्:—

सौंपे जाने वाले कार्य

आयोग, पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और जो,—

- (क) (एक) राज्य द्वारा उद्गृहीत करें, शुल्कों, पथकों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच, जो भारत के संविधान के भाग 9 तथा 9-क के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को;
- (दो) ऐसे करें, शुल्कों, पथकों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेगी, या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेगी;
- (तीन) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;
- (ख) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में;

राज्यपाल को अनुशंसा करेगा.

(2) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में, आयोग अपनी अनुशंसाएं करते समय निम्नलिखित अन्य विषयों पर विचार करेगा:—

- (एक) भूमि पर देय करों एवं भूमि में संव्यवहारों की लिखतों पर देय स्टाम्प शुल्क से राजस्व के शुद्ध आगमों के स्थानीय नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को न्यागमन;
- (दो) पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय पर कर से राजस्व के शुद्ध आगमों के स्थानीय नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को न्यागमन;
- (तीन) माल और सेवा कर से राजस्व के शुद्ध आगमों के स्थानीय नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों को न्यागमन;
- (चार) राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग को निर्दिष्ट किये गये किसी अन्य विषय में.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

पृ. क्र. 257-25-2017-आनीविड-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 4th October 2017

No. 256-25-2017-EPAU-IV.— In pursuance of article 243-I and article 243-Y of the Constitution of India read with Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994) and in continuation of this department's Notification No. 66-25-2017-EPAU-IV dated 20th March, 2017, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, determines the following Terms of Reference for consideration of the Fifth State Finance Commission, namely:—

Terms of Reference

The Commission shall review the financial position of the Panchayats and Municipalities and make recommendations to the Governor as to—

(a) the principal which should govern—

- (i) the distribution between the States and the Panchayats and the Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the State, which may be divided between them under part IX and IX-A of the Constitution of India and the allocation between the Panchayats and Municipalities at all levels of their respective shares of such proceeds;
- (ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to, or appropriated by the Panchayats and Municipalities;
- (iii) the grants-in-aid to the Panchayats and Municipalities from the Consolidated Fund of the State;

(b) the measures needed to improve the financial position of the Panchayats and Municipalities

2. in the interests of sound finance of the Panchayats and Municipalities, the Commission while making its recommendations will consider the following other matters:—

- (i) the devolution to urban local bodies and Gram Panchayats out of the net proceeds of revenue from tax on land and Stamp Duty paid on the instruments of transactions in land,
- (ii) the devolution to urban local bodies and Gram Panchayats out of net proceeds of revenue from tax on sale of petroleum products;
- (iii) the devolution to urban local bodies and Gram Panchayats out of net proceeds of revenue from Goods and Services Tax;
- (iv) any other matters referred to the State Finance Commission by the Governor.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIRUDHE MUKERJEE, Principal Secy.